



नईदुनिया

वैश्विक हलचल, कच्चा तेल और अमेरिकी महंगाई तय करेंगे शेयर बाजार की दिशा

विशेषज्ञों ने विदेशी निवेश और वैश्विक संकेतों पर भी नजर रखने की सलाह दी

मुंबई

इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार की चाल पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संघर्ष, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और अमेरिका के आगामी मुद्रास्फीति आंकड़ों से तय होगी। जो विश्लेषकों का मानना है कि इन वैश्विक घटनाक्रमों के साथ-साथ विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और अन्य वैश्विक संकेतों

पर भी बाजार की गहरी नजर रहेगी।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक आंकड़े भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होंगे। बाजार के जानकारों ने कहा कि इस सप्ताह बाजार वैश्विक मौद्रिक नीति, कच्चे तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर संवेदनशील रह सकता है।

उन्होंने विशेष रूप से होमजु जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रमों को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इनका भारत महंगाई, बाहरी संतुलन और कंपनियों की लाभप्रदता पर सीधा असर पड़ सकता है।

एनरिक मनी के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पिछले सप्ताह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में आठ प्रतिशत से अधिक और डब्ल्यूटीआई में नौ प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होमजु जलडमरूमध्य को लेकर बनी चिंताओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भू-राजनीतिक जोखिमों को बढ़ा दिया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों ऊंची बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, निवेशकों की नजर अमेरिका के उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व की सितंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक को लेकर

बदलती उम्मीदों पर रहेगी।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के आगामी महंगाई आंकड़े फेडरल रिजर्व की नीतिगत दिशा और वैश्विक बाजार धारणा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये आंकड़े अमेरिकी बान्ड प्रतिफल और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों को भी प्रभावित करेंगे। घरेलू मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह, रुपये की चाल और बाजार में नकदी की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी।

पिछले सप्ताह, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 749.08 अंक यानी 0.96 प्रतिशत के नुकसान में रहा था।

न्यूज़ब्रीफ

जनधन योजना में चुनौती: करोड़ों खाते निष्क्रिय, लाखों में नहीं है कोई राशि, आरटीआई से खुलासा; देश में 15 करोड़ से अधिक खाते निष्क्रिय



जयपुर। प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत वित्तीय समावेशन के प्रयासों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) के जवाब से खुलासा हुआ है कि देश में करीब हर चौथा जनधन खाता निष्क्रिय है, जबकि करोड़ों खातों में कोई राशि जमा नहीं है। ये आंकड़े योजना की प्रभावशीलता और जमीनी स्तर पर इसके उपयोग पर सवाल खड़े करते हैं। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को दी गई जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त तक देशभर में पीएमजेडीवाई के कुल 59.03 करोड़ से अधिक खाते थे, जिनमें 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा थी। हालांकि, वित्तजनक बात यह है कि इन खातों में से 15.36 करोड़ खाते निष्क्रिय पाए गए। इसके अलावा, 5.72 करोड़ से अधिक खातों में कोई राशि जमा नहीं थी, यानी वे शून्य-बैलेंस वाले खाते हैं। अगस्त, 2014 में वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंक खाते तक पहुंच प्रदान करना है।

घरेलू एलपीजी के दाम स्थिर, आम जनता को मिली राहत, 19 किलो वाले सिलेंडर में मामूली वृद्धि से होटल-रेस्टोरेंट का बजट बिगड़ा



मुंबई। भारत में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतें पूरी तरह स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम जनता और परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की तेल मार्केटिंग ने घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, कर्मशियल इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के बड़े गैस सिलेंडरों की कीमतों में 1 सितंबर को 9.50 से 11.50 रुपये प्रति सिलेंडर की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसका असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग बिजनेस पर पड़ रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने आम उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रखे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 95 डालर प्रति बैरल से ऊपर निकल जाने और आयात लागत बढ़ने के कारण ही वाणिज्यिक गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। वर्तमान में, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और मुंबई में 941.50 रुपये पर उपलब्ध है, जबकि कर्मशियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2,747.50 रुपये है। इस बीच पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीएसी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच घरेलू एनपीजी की खपत 15.9 फीसदी 11.3 मिलियन टन रह गई है। देश में तेजी से फैल रहा पीएनजी नेटवर्क, 940 से 1000 रुपये के बीच का मौजूदा उच्च बेस प्राइस और सब्सिडी खत्म होने या कम होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन की ओर वापसी, इस गिरावट के मुख्य कारण हैं।

फाक्सवेगन की सबसे बड़ी छंटनी: 1 लाख नौकरियों पर संकट



बर्लिन। जर्मनी की दिग्गज कार कंपनी फाक्सवेगन अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है, जिसने इस दशक के अंत तक करीब 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। यह वैश्विक आटो उद्योग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है। कंपनी के कुल वैश्विक कार्यबल का करीब 15 प्रतिशत प्रभावित होगा, जिसमें पहले से तय 50,000 नौकरियों की कटौती के अतिरिक्त अब 50,000 और पद समाप्त किए जाएंगे। इस कड़े कदम के पीछे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की धीमी पड़ती मांग और चीन से मिल रही कड़ी चुनौती को मुख्य वजह बताया जा रहा है।

अगले सप्ताह 15 नए आईपीओ की लान्चिंग, 9 शेयरों की होगी लिस्टिंग

नई दिल्ली

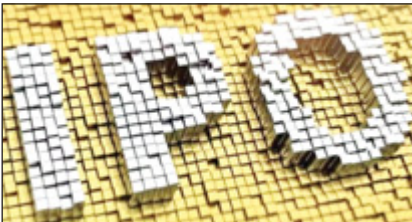
कारोबारी सप्ताह के दौरान प्राइमरी मार्केट में अच्छी हलचल रहने वाली है। इस सप्ताह 15 कंपनियां अपने आईपीओ लान्च कर रही हैं। इनमें 11 कंपनियों के आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट के हैं, जबकि शेष चार आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। इसके अलावा पिछले सप्ताह चार सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुले एकआईपीओ में भी इस सप्ताह आठ सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। जहां तक नई लिस्टिंग की बात है, तो इस सप्ताह नौ कंपनियां स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। इनमें तीन कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की जबकि शेष छह कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं।

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सात सितंबर को ग्रणव कंस्ट्रक्शंस का 351.03 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में नौ सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 118 रुपये प्रति शेयर से लेकर 124 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 120 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 15 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सात सितंबर को ग्रणव कंस्ट्रक्शंस का 351.03 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में नौ सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 118 रुपये प्रति शेयर से लेकर 124 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 120 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 15 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

इसी दिन अपना लाजिस्टिक्स का 34.14 करोड़ रुपये का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में भी नौ सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 60 रुपये प्रति शेयर का फाइन इश्यू प्राइस तय किया गया है, जबकि लाट साइज 2,000 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 15 सितंबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

इसके अगले दिन आठ सितंबर को कनोहर इलेक्ट्रिकल्स का 1,055.74 करोड़ रुपये का आईपीओ



सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में 10 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 601 रुपये प्रति शेयर से लेकर 632 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 23 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 16 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

इसी दिन प्रसोल केमिकल्स का 500 करोड़ रुपये का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में भी दस सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 643 रुपये प्रति शेयर से लेकर 676 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 22 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 16 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

आठ सितंबर को ही ग्लास वाल सिस्टम्स का 427.89 करोड़ रुपये का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में भी 10 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 172 रुपये प्रति शेयर से लेकर 182 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 82 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 16 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

इसके अगले दिन सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन नौ सितंबर को रेंटोमोजो लिमिटेड का 1,255.57 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में 11 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 384 रुपये प्रति शेयर से लेकर 404 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 37 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 17 सितंबर को बीएसई और

एफपीआई ने सितंबर के पहले सप्ताह में निकाले 10,289 करोड़ रुपये



मुंबई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में 10,289 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। शुद्ध बिकवाली बाजार में लगाई गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है। तीन महीने लगातार पूंजी लगाने के बाद एफपीआई बाजार में बिकवाल दिखे हैं। इससे पहले अगस्त में उन्होंने 25,492 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। जुलाई में उन्होंने 40,031 करोड़ रुपये और जून में 4,669 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। सितंबर में अबतक एफपीआई ने इक्विटी में 7,443 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। डेट और हाइब्रिड उपकरणों में भी उनका निवेश नकारात्मक रहा है यानी कम हुआ है जबकि म्यूचुअल फंड में वे शुद्ध रूप से लिवाल रहे हैं। हाइब्रिड उपकरणों से एफपीआई सितंबर में अब तक 2,522 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। डेट से उन्होंने 390 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। वहीं म्यूचुअल फंड में एफपीआई ने 67 करोड़ रुपये लगाये हैं। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में एफपीआई ने अब तक 1,57,639 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। इसमें अकेले इक्विटी से उन्होंने 2,31,886 करोड़ रुपये की निकासी की है।

खाद्य तेलों का मिलाजुला रुख, कहीं उछाल तो कहीं गिरावट

आयातकों की लागत से नीचे बिकवाली से सोयाबीन तेल टूटा, औद्योगिक मांग ने पाम-पामोलीन को सहाय दिया

नई दिल्ली

बीते सप्ताह खाद्य तेल बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जहां आयातकों द्वारा लागत से नीचे बिकवाली के दबाव में सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई, वहीं औद्योगिक मांग बढ़ने से कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन के दाम में तेजी दर्ज की गई। घरेलू मंडियों में सोयाबीन तिलहन की कम आवक के चलते इसमें मामूली सुधार हुआ, जबकि सरसों और मूंगफली तेल-तिलहन के दाम स्थिर बने रहे। बाजार सूत्रों के अनुसार, मंडियों में सोयाबीन की आवक घटकर 40-45 हजार बोरी रह गई, जो दैनिक मांग



(2.5-3 लाख बोरी) से काफी कम है। इसके बावजूद, आयातक बैंकों में अपने ऋण साख-पत्र चालू रखने के लिए लागत (125 रुपये/किलो) से

लगभग 5 फीसदी नीचे, 118.50 रुपये/किलो पर सोयाबीन तेल बेच रहे हैं। यह उनकी गंभीर आर्थिक स्थिति दर्शाता है, जिसके चलते सोयाबीन

तेल में गिरावट आई। ऊंची कीमतों पर कमजोर मांग से बिनौला तेल भी सस्ता हुआ। दूसरी ओर, बढ़ती औद्योगिक मांग और अन्य खाद्य तेलों से सस्ता होने के कारण पाम-पामोलीन में मजबूती देखी गई। ऊंचे दाम पर सुस्त कारोबार के बीच सरसों एवं मूंगफली तेल-तिलहन के दाम में स्थिरता बनी रही। बीते सप्ताह सरसों दाना 8,300-8,350 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों तेल दादरी 16,800 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों पक्की एवं कच्ची घानी तेल क्रमशः 2,735-2,835 रुपये और 2,735-2,885 रुपये टिन (15 किलो) पर स्थिर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमशः 25-25 रुपये सुधार के साथ क्रमशः 6,700-6,750 रुपये और 6,550-6,650 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, आयातकों की लागत से नीचे दाम पर बिकवाली की वजह से दिल्ली में सोयाबीन तेल 150 रुपये की गिरावट के साथ 15,600 रुपये

प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 150 रुपये की गिरावट के साथ 15,400 रुपये और सोयाबीन डीमग तेल 200 रुपये की गिरावट के साथ 11,850 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 7,350-7,925 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 17,000 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंडर रिफाईंड तेल 2,680-2,980 रुपये प्रति टिन पर स्थिर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सीपीओ तेल का दाम 150 रुपये के सुधार के साथ 14,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली 150 रुपये के सुधार के साथ 16,000 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 100 रुपये के सुधार के साथ 14,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। औद्योगिक मांग होने के बावजूद ऊंचे दाम पर कामकाज प्रभावित रहने से बीते सप्ताह बिनौला तेल का दाम 400 रुपये की गिरावट के साथ 16,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

केला निर्यात बढ़ाने को एफडीआई में ढील, बागान क्षेत्र में उदार होंगे नियम



नई दिल्ली

सरकार देश के बागान क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को और उदार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसका

मुख्य लक्ष्य केले जैसी अन्य

वाणिज्यिक फसलों को भी

एफडीआई के दायरे में लाकर

उनके निर्यात को बढ़ावा देना

है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

इस संबंध में विभिन्न

हितधारकों के साथ परामर्श कर

रहा है। वर्तमान में, चाय,

काफी, रबड़, इलायची, पाम

और जैतून के पेड़ों के बागानों में

स्वतः मंजूर मार्ग से 100

प्रतिशत विदेशी निवेश की

अनुमति है, जबकि अन्य

बागान गतिविधियों को इससे

बाहर रखा गया है।

वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्यिक फसलों को

एफडीआई के दायरे में

लाने पर कर रहा विचार

सरकार अब इस दायरे का विस्तार कर केले जैसी फसलों को शामिल करने की संभावनाएं तलाश रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, जहां सालाना तीन करोड़ टन से अधिक उत्पादन होता है, लेकिन वैश्विक निर्यात बाजार में इसकी हिस्सेदारी मात्र एक प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 37.75 करोड़ डालर मूल्य के केले का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष से 30 फीसदी अधिक था। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इसे एक अरब डालर तक पहुंचाना है। एफडीआई से प्रसरण, पैकेजिंग और लाजिस्टिक्स में निवेश बढ़कर निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, वहीं ईरान, इराक, यूएई जैसे मौजूदा बाजारों के अलावा अमेरिका, रूस और जापान में भी निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं।

टाटा मोटर्स का इटली के इवेको ग्रुप के लिए 34,000 करोड़ का अधिग्रहण ऑफर

3.82 अरब की डील से ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा दबदबा

नई दिल्ली

टाटा मोटर्स ने वैश्विक वाणिज्यिक वाहन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कंपनी ने इटली की मशहूर कर्मशियल व्हीकल कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने के लिए एक आठ-कैश वालंटरी टेंडर आफर पेश किया है। यह महत्वाकांक्षी अधिग्रहण लगभग 3.82 अरब यूरो (लगभग 34,000 करोड़ रुपये) का है, जिससे भारतीय आटोमोबाइल दिग्गज का वैश्विक दबदबा काफी बढ़ जाएगा। टाटा मोटर्स अपनी नीदरलैंड्स स्थित कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग बीवी के माध्यम से इवेको ग्रुप के सभी शेयर खरीदने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आई है। कंपनी ने इवेको के एक शेयर की कीमत 14.10 यूरो तय की है। इस सौदे को इटली के मार्केट रेग्युलेटर कान्साब से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जो इसकी राह आसान कराता है। टाटा मोटर्स और इवेको ग्रुप के संयुक्त बयान के अनुसार, यह टेंडर आफर 7 सितंबर से 26 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इवेको ग्रुप के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने इस सौदे को अपनी पूरी मंजूरी देते हुए शेयरधारकों से आफर स्वीकार करने की सिफारिश की है। इवेको की सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी एक्सोर, जिसके पास 27.06 फीसदी कामन शेयर और



43.19 फीसदी वोटिंग अधिकार हैं, उसने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने का वादा किया है। इस स्थिति के बाद वैश्विक कर्मशियल व्हीकल मार्केट में एक नया और मजबूत मंच तैयार होगा। अनुमान है कि संयुक्त इकाई की सालाना बिक्री 95,00,000 यूनिट्स से अधिक और कुल राजस्व लगभग 21 अरब यूरो (लगभग 2.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) होगा। खास बात यह है कि दोनों कंपनियों के कारोबार और भौगोलिक मौजूदगी में कोई टकराव नहीं है, जिससे एसवायएनइआरजीवाय का पूरा लाभ मिलेगा। नई इकाई के राजस्व का विवरण काफी संतुलित

होगा, जिसमें यूरोप से लगभग 46 फीसदी, भारत से करीब 32 फीसदी, दक्षिण अमेरिका से 8 फीसदी और बाकी दुनिया के बाजारों से लगभग 14 फीसदी राजस्व आने की उम्मीद है। यह एकीकरण दोनों कंपनियों को लागत और अनुसंधान खर्चों को बड़े पैमाने पर साझा करने, परिचालन क्षमता में सुधार करने और कर्मशियल व्हीकल सेक्टर के उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद करेगा। सौदे को पूरा करने के लिए कम से कम 95 फीसदी कामन शेयरों की मंजूरी आवश्यक है, हालांकि कुछ शर्तों के तहत यह 80 फीसदी तक घट सकती है।